

278

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012

1. गौरैलाल पुत्र श्री तिजवा पाल
2. लछुवा पुत्र श्री दोलता पाल,
निवासीगण- ग्राम छन्नापुरवा, तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)

—आवेदकगण

बनाम

सुखिया पुत्र उरुआ चमार, निवासी-ग्राम
मियाताल, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर
(म.प्र.) —अनोवेदक

श्री अमित भार्गव, आ/म/१०

द्वारा आज दि 30-7-12 को

प्रस्तुत

30-7-12

बलक ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/निगरानी/अ-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26/06/2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 50 (1) के अधीन पुनरीक्षण। माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, अनावेदिका तहसील न्यायालय के समक्ष सर्वे क्रमांक-3/1/5, एकवा 2.023 हेक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन किया। नायब तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
2. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण सरहदी काश्तकार हितव्य व्यक्तियों को सूचना दिये बिना एकपक्षीय सीमांकन कर दिनांक 03/08/2008 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, कब्जा एवं नक्शे की तरमीम यथारिथति नहीं है, भिन्नता है। अतः नक्शे में 3/1/5, 3/7 एवं 3/9/1 की तरमीम निरस्त करके पेंसिली तरमीम अनुसार तरमीम स्वीकृत कर सीमांकन करना उचित होगा। अन्यथा आवेदक एवं सरहदी कृषक अपना अपना कब्जा नहीं छोड़ने चाहते हैं। अर्थात् राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा त्रुटिपूर्ण पाया गया एवं

अमित भार्गव
(अ/म/१०)

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-2385-दो/2012

जिला-छतरपुर

गौरेलाल व अन्य विरुद्ध सुखिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 87/निग./अ-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0क0 जैन) सहस्य 18/03/19</p>